लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3847

जिसका उत्तर बुधवार, 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

3847. श्री जिया उर रहमान:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनाज, दालों, सब्जियों और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन सी नीतियां क्रियान्वित की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग) : उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीतिगत साधनों में परिवर्तन पर उचित निर्णय लिए जा सकें।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अंशांकित और लक्षित रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में, बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। बफर से प्याज को थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केन्द्रों पर स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। इन उपायों से दालें, चावल, आटा और प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिली है।

गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात एएवाई परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता प्राप्त घरों के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

भारत घरेलू एलपीजी की खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत पर निर्भर है। सरकार घरेलू एलपीजी के संबंध में उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को संशोधित करती रहती है। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 64% की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से नवंबर 2024 में 632 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक) जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के लिए प्रभावी मूल्य भारत में 44% कम हो गया (अगस्त 2023 में 903 रुपये से नवंबर 2024 में 503 रुपये तक)।

सरकार ने 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा विक्रय मूल्य में 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर कटौती की है और 9 मार्च, 2024 से 100 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर कटौती की है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खुदरा विक्रय कीमत वर्तमान में 803 रुपये है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी के बाद, भारत सरकार 503 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) की प्रभावी कीमत पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। कुछ राज्य सरकारें एलपीजी रिफिल पर कुछ अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही हैं और अपने संबंधित बजट से अतिरिक्त लागत का वहन कर रही हैं।

****